



## तीरंदाज

- अश्विनी भटनागर**

एक तो अति विस्तृत, अगम्य अंधकारमय जंगल, उस पर रात्रि का समय। पतंग उस जंगल में रहते है, लेकिन कोई चू त कहीं नहोलाता है। शब्दमय पृथ्वी की निस्तब्धता का अनुमान किया नहीं जा सकता है; लेकिन उस अनंत शून्य जंगल के सूचीभेध अंधकार का अनुभव किया जा सकता है। सहसा इस रात के समय की भयानक निस्तब्धता को भेद कर ध्वनि आई, ‘मेरा मनोरथ क्या सिद्ध न होगा?’

इस तरह तीन बार वह निस्तब्ध अंधकार आलोड़ित हुआ, ‘तुम्हारा क्या प्रण है?’ उतर मिला, ‘मेरा प्रण ही मेरा जीवन सर्वस्व है।’

प्रतिशब्द हुआ, ‘जीवन तो तुच्छ है, सब इसका त्याग कर सकते है।’

‘तब और क्या है... और क्या होना चाहिए?’

उत्तर मिला, ‘भक्ति।’

संन्यासी आंदोलन और बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि पर लिखी बाकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की कालजयी कृति ‘आनंदमठ’ की शुरुआत इस प्रकरण से होती है। आनंदमठ 1882 में छपी थी। राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व की प्रधानता के भाव की वजह से इस कृति का विशिष्ट स्थान है। इसके एक गीत ‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी प्राप्त है।

बाकिमचंद्र की कहानी सूखा ग्रस्त बंगाल के एक गांव पदचिह्ना से शुरू होती है, जहां के जमींदार महेंद्र सिंह अपनी बदहाली से त्रस्त होकर अपनी पत्नी कल्याणी और बेटी सुकुमारी के साथ भोजन की व्यवस्था करने के लिए घर से निकलते हैं, पर अप्रत्याशित उनसे बिछड़ जाते हैं। कल्याणी कुछ डकैतों के चुंगल में फंस जाती है, पर जल्द ही वहां से बच निकलती है। उसकी मुलाकात सत्यानंद से होती है, जो आनंदमठ के प्रधान हैं। वे कल्याणी को अपने मठ में शरण देते हैं और अपने संन्यासी साथी भवानंद को महेंद्र सिंह को ढूंढ़ने भेज देते हैं।

इस बीच ईस्ट इंडिया कंपनी का राजस्व कलकत्ता भेजा जा रहा था और अंग्रेज फौजें जंगल में चौकसी कर रही थीं। महेंद्र और भवानंद को जंगल में घूमता देख कर वे दोनों को पकड़ लेती हैं।

उनकी बंदी अवस्था के चलते, संन्यासियों का एक जत्था कंपनी के राजस्व को लूटने के लिए हमला करता है और उन्हें छुड़ा लेता है। मठ की तरफ जाते हुए महेंद्र भवानंद को लूट और हत्या के लिए धिक्कारता है, पर उसकी बातों का जवाब देने के बजाय भवानंद वंदे मातरम गा उठता है।

अपनी धरती को मां की तरह पहचानने का पाठ महेंद्र आनंदमठ में रह कर पढ़ता है और जल्दी ही वह संन्यासियों से एक हो जाता है। वह भी अपनी धरती मां का गौरव और प्रतिष्ठा और उसकी

# विज्ञान शिक्षा की बुनियाद

### प्रेमपाल शर्मा

समाज का विकास विज्ञान के विकास के समांतर हुआ है। इस बात को और विस्तार दें तो सुख, समृद्धि, शांति दुनिया भर में विज्ञान से ही आई है। दुनिया के सभी विकसित, उन्नत राष्ट्र इसीलिए विज्ञान का महत्त्व समझते हैं और इसीलिए अग्रणी बने हुए हैं। गौरतलब है कि पचास के दशक में रूस ने अंतरिक्ष विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में जैसे ही लंबी छलांग लगाई, अमेरिका में हलचल मच गई। वहां तुरंत विज्ञान पढ़ने-पढ़ाने और शोध को राष्ट्रीय प्राथमिकता में रखा गया और दूसरे विश्वयुद्ध के बाद उस शीत युद्ध में धीरे-धीरे अमेरिका विज्ञान के बूते ही बाजी मारता चला गया। न केवल दूसरे विश्वयुद्ध के दौर से जर्मनी के वैज्ञानिक आइंस्टाइन आदि अमेरिका पहुंचते चले गए, बल्कि उसके बाद से आज तक अमेरिका दुनिया के वैज्ञानिकों की पहली प्राथमिकता बना हुआ है। भारत के हरोगविंद खुराना,

चंद्रशेखर, वैकटराम कृष्णा आदि अमेरिकी शिक्षा के बूते ही दुनिया में नाम कमा पाए हैं। हम लगभग तीस वर्ष से लगातार यह देखते-सुनते आ रहे हैं कि चीन के विश्वविद्यालय विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पेटेंट और नई खोजों के पैमानों से नापा जाए तो आज चीन की स्थिति अमेरिका से भी आगे है। विज्ञान और तकनीक के बूते ही छोटा-सा इजराइल कैसे अपनी धाक जमाए हुए है। जापान तो है ही पिछले लगभग सौ सालों से सबसे मजबूत। पड़ोसी चीन की ही बात करें, तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक को बदला है और इसीलिए दुनिया भर के शीर्ष सौ विश्वविद्यालयों में पांच से ज्यादा चीन के होते हैं और हम पहले पांच सौ में भी मुश्किल से आ पाते हैं।

आजादी के बाद नारों और दीवारों पर तो वैज्ञानिक चेतना की बातें कही गईं, लेकिन न शिक्षा में कोई बुनियादी परिवर्तन आया और न इसी वजह से समाज में। माना हम बड़ा देश है, यहां कई जटिलताएं हैं, लेकिन अगर अंधेरा बढ़ता ही जाए, तो हमें पूरी नीति की समीक्षा की जरूरत है। पिछली सरकार ज्ञान आयोग और उसकी अंग्रेजी पड़ाने, लादने की जिद से इतनी व्यस्त थी कि सरकारी शिक्षा निजी स्कूलों की तरफ तो चली गई, उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं मिला। यानी अंग्रेजी ठीक करने के चक्कर में दुनिया के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में हम और पीछे होते गए। इसलिए पहले तो यह भ्रम हटाना होगा कि अंग्रेजी के बूते आप विश्वविद्यालयों को ठीक कर सकते हैं। कम से कम वर्तमान सरकार अंग्रेजी की वैसी दीवानी नहीं है और अगर विज्ञान को सही समझ पाए, तो मजबूत इच्छाशक्ति भी रखती है।

मौजूदा सरकार के पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं। निश्चित रूप से समझने में समय लगता है, लेकिन बड़े परिवर्तन उस प्रक्रिया से ही संभव है जैसे दुनिया के राष्ट्रों ने संभव किए हैं। पांच सौ वर्ष पहले का यूरोप इसी विज्ञान के बूते भारत, चीन जैसी पुरानी सभ्यताओं को पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया और आज भी उसी रफतार से आगे बढ़ रहा है। सभ्यता तो चीन की भी पुरानी है, लेकिन उसे मौजूदा विज्ञान से कोई परहेज नहीं है। उसने मौजूदा विज्ञान के बूते अपनी स्थिति बहुत मजबूत की है। हमारा अतीत निश्चित रूप से गौरवशाली रहा है। शून्य की खोज, आर्सेनिक, वराहमिहिर, सुश्रुत के कामों पर हमें गर्व है, लेकिन आज तक हमें फिर से आगे होना है, तो कुछ अपनी पुरानी सभ्यताओं से उठाएं, उन्हें जाँचें-परखें, दुनिया के सामने प्रमाणित करें और साथ ही

दुनिया के अनुभवों को साथ लेकर आगे बढ़ें। हम महान थे, विज्ञान ऐसी किसी स्थापना को नहीं मानता। यह बार-बार उसका प्रमाण माँगता है। और इसके लिए हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में पूरा बदलाव चाहिए। विज्ञान श्रद्धा, भक्ति का नाम नहीं है। विज्ञान की शुरुआत ही शंका, संदेह से होती है। यह उसकी बुनियाद है। डाल्टन ने कहा- एटम सबसे छोटी इकाई है। दूसरे विज्ञानकों ने उसे तोड़ दिया कि नहीं, छोटी इकाईं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। दूसरे वैज्ञानिकों ने उसे और विखंडित कर दिया। विज्ञान की लाखों बातें ऐसे ही प्रश्नों, शंकाओं, बहसों से आगे बढ़ी हैं।

हर धर्म और उसकी बातें निजीजीवता की हद तक वहीं खड़ी रहती हैं, जबकि विज्ञान निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है। इस पक्ष पर तुरंत काम करने की जरूरत है। स्कूली बच्चे तर्कशिल बनेंगे, अपने आसपास की समस्याओं पर प्रश्न करना, उनसे जूझना सीखेंगे, उनके हल निकालेंगे और इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए हमारे विश्वविद्यालय दुनिया की खोजों से सरीखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर जरूरत हो तो पांच वर्ष तक सिर्फ विज्ञान की शिक्षा ही दी जाए, तो देश का कायापलट हो सकता है। यह केवल शिक्षा का मामला नहीं है, पूरे समाज को बदलने के लिए ऐसे ही कदमों की जरूरत है।

बुनियादी सामाजिक प्रश्न की तरफ लौटते हैं। जाति और धर्म के भेद-विभेद और उनसे उत्पन्न समस्याओं से पूरा देश जूझ रहा है। विज्ञान की समझ कहती है कि न केवल मनुष्य, बल्कि सभी जीवधारियों के सतानबे फीसद जीन समान होते हैं, यानी तीन फीसद की भिन्नता ही करोड़ों जीवों को अलग करती है। तो फिर मनुष्य की जाति, धर्म के भेद क्या नकली, बनावटी नहीं है? जब ऐसी तार्किक स्थापना हमारे बचपन में बैदा दी जाए, तो उसे कोई भी राजनीति, कोई भी धर्मगुरु अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता।

इन्हीं सब कारणों से संयुक्त राष्ट्र ने 2001 से दुनिया भर में विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष दस नवंबर को मनाने का फैसला किया, जिससे कि सभी देश विज्ञान के तार्किक रास्ते से सुख, समृद्धि और विकास की तरफ अग्रसर हो सकें। क्या तीन सौ वर्ष पहले हम इतने सुखीं थे? चेचक से लाखों मर जाते थे। इंग्लैंड के डॉक्टर जीनर ने रास्ता खोजा और पूरी दुनिया आज चेचक से मुक्त हो गई है। क्या यह किसी माता, देवी या पीर-पैगंबर की पूजा से संभव हो सकता है? पोलियो का कीटाणु दुनिया भर में लाखों लोगों को पंगु बना देता था, आज हम उससे मुक्त हैं। पेंसिलीन, हैजा के टीके, बड़ी से बड़ी सर्जरी, केसर से पार पाना, यानी विज्ञान के बूते दुनिया आराम की जिंदगी जी रही है और इसीलिए मनुष्य की औसत आयु निरंतर बढ़ रही है। भारत का ही उदाहरण लें, तो आजादी के वक्त औसत आयु सिर्फ बर्तीस वर्ष थी, आज सत्तर वर्ष के करीब है। यह सिर्फ विज्ञान ने संभव करके दिखाया है। इसलिए सभी सरकारों का दायित्व है कुछ दिनों के लिए दूसरी बहसों को एक तरफ रख कर सिर्फ विज्ञान में दुनिया के देशों की बराबरी करने की तरकीब निकालें। इससे हमारे समाज में तो बुनियादी परिवर्तन आएगा ही, हमें अरबों रुपए के हथियार भी आयात नहीं करने पड़ेंगे, और न जीवन रक्षक दवाएं आयात करने होंगी, जो हमारी अर्थव्यवस्था को कमर तोड़ रही हैं।

विज्ञान शिक्षा की तार्किकता और दर्शन से हमारे सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान के शोध भी बदलेंगे और सही मायनों में हमारे विश्वविद्यालय भी। फिर हमारे बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड नहीं भागेंगे। हमारे अतीत में जो भी विज्ञान की कसौटी पर अच्छा है उसे भी सहर्ष अपनाएं और दुनिया के मौजूदा ज्ञान को भी।

# ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग !

संपन्नता को पुन:स्थापित करने का व्रत लेता है। अंत में, सत्यानंद के नेतृत्व में संयासी समुदाय अंग्रेजी फौज को बुरी तरह परास्त करता है और खजाना अपने आधीन कर लेता है। यह परम वीरता और उल्लास का क्षण था, जिसमें हिंदू राष्ट्र की पहली स्वर्णिम किरण क्षितिज पर साफ दिख रही थी, पर आनंदमठ की कहानी एक आखिरी मोड़ लेती है।

अंतिम अंश इस प्रकार है :
‘चिकित्सक बोले- ‘सत्यानंद! आज माघी पूर्णिमा है।’
सत्यानंद- ‘चलिए मैं तैयार हूं। किंतु महात्मन्! मेरे एक संदेह को दूर कीजिए। मैंने क्या इसीलिए युद्ध-जय कर सनातन-धर्म की पताका फहराई थी?’

जो आए थे, उन्होंने कहा- ‘तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, मुसलिम राज्य ध्वंस हो चुका।

### सत्यानंद की दोनों आंखों से जलधारा बहने लगी। उन्होंने सामने जननी-जन्मभूमि की प्रतिमा की तरफ देख, हाथ जोड़ कर कहा- ‘हाय माता! तुम्हारा उद्धार न कर सका। तू फिर म्लेच्छों के हाथ में पड़ेगी। संतानों के अपराध को क्षमा कर दो मां। रणक्षेत्र में मेरी मृत्यु क्यों न हो गई?’

अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं, अनर्थक प्राणहत्या की आवश्यकता नहीं!’
सत्यानंद- ‘मुसलिम राज्य ध्वंस अवश्य हुआ है, किंतु अभी हिंदू राज्य स्थापित हुआ नहीं है। अब भी कलकत्ते में अंगरेज प्रबल है।’

वे बोले- ‘अभी हिंदू-राज्य स्थापित न होगा। तुम्हारे रहने से अनर्थक प्राणी-हत्या होगी, अतएव चलो!’
यह सुन कर सत्यानंद तीव्र मर्म-पीड़ा से कातर हुए, बोले- ‘प्रभो! यदि हिंदू-राज्य स्थापित न होगा, तो कौन राज्य होगा, क्या फिर मुसलिम-राज्य होगा?’

उन्होंने कहा- ‘नहीं, अब अंगरेज-राज्य होगा।’
सत्यानंद की दोनों आंखों से जलधारा बहने लगी। उन्होंने सामने जननी-जन्मभूमि की प्रतिमा की तरफ देख हाथ जोड़ कर कहा- ‘हाय माता! तुम्हारा उद्धार न कर सका। तू फिर म्लेच्छों के हाथ में पड़ेगी। संतानों के अपराध को क्षमा कर दो मां। रणक्षेत्र में मेरी मृत्यु क्यों न हो गई?’

महात्मा ने कहा- ‘सत्यानंद कातर न हो। तुमने बुद्धि विप्रम से दरस्य वृत्ति द्वारा घन संचय कर रण में विजय ली है। पाप का कभी पवित्र फल नहीं होता। अतएव तुम लोग देश-उद्धार नहीं कर सकोगे। और अब जो कुछ होगा, अच्छा होगा। अंगरेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार नहीं हो सकेगा। महापुरुषों ने जिस प्रकार समझाया है, मैं उसी प्रकार समझाता हूँ- ध्यान देकर सुनो। तैतीस कोटि देवताओं का पूजन सनातन धर्म नहीं है। वह एक तरह का लौकिक निकृष्ट-धर्म है, हिंदू धर्म लुप्त हो गया है। प्रकृति हिंदू धर्म

### जिस दिन महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे आए थे पिछले सप्ताह, मीर तकी मीर का एक शेर बहुत गूदर आया मुझे। यह शेर है : ‘जिस पर कौंटो उद्योग में हजारों नौकरियों के जाने की। जब पंजाब और महाराष्ट्र कोआर्परेटिव बैंक (पीएमसी) में घोडला सामने आया और लोगों के इस सद्मे से मरने की खबरें आने लगीं, तो

जब प्रधानमंत्री ने उस शाम को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय कहा कि उनको गर्व होना चाहिए कि इन दोनों राज्यों में पांच साल काम करने के बाद उनकी सरकारें फिर से लौट कर आई हैं। यथार्थ कुछ और है और ऐसा लगा जैसे मोदी इस यथार्थ का सामना करने के बजाय उससे दूर भागना चाहते हैं। क्या इसलिए कि उनको भी अहसास होने लगा है कि सत्ता नाजुक चीज है? कहने को तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है दोनों राज्यों में, लेकिन इन जाीत का विरलेषण अगर किया जाए, तो साफ दिखने लगते हैं इस जीत में हार के कुछ छिपे हुए आसार। इसलिए कि जबसे नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है तबसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में एक

अजीब-सा घमंड नजर आने लगा है जैसे कि अब उनको हराने वाला कोई नहीं रहा है। यह घमंड चुनाव अभियान में अहंकार बन गया था, जिसके कारण ऐसा लगा जैसे जमीन से इन आला नेताओं का रिश्ता टूट गया हो। सो, जहां सबसे बड़े मुद्दे थे आर्थिक मंदी से जुड़े हुए, वहां चुनाव अभियान का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने को। प्रधानमंत्री ने अपने हर भाषण में अपने प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती दी कि अगर इस धारा को हटाना उनको पसंद नहीं है तो खुल कर क्यों नहीं कहते हैं कि इसके वापस लाएं। जवाब उनको मिला शरद पावर से, जिन्होंने कहा कि इसके हटने न हटने से महाराष्ट्र को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस राज्य के किसानों में क्षमता ही नहीं है कश्मीर में जाकर जमीन खरीदने की। महाराष्ट्र में रहती हूं, सो यकीन मानिए जब मैं कहती हूं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने बहुत कोशिश की अनुच्छेद 370



## वक्त की नब्ज

- तवलीन सिंह**

महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हथियार बना कर इस्तेमाल करना गलत था। ऐसा करने से सवाल पूछने वालों की तादाद बढ़ी है।

आर्थिक मंदी और भी बड़ा मुद्दा बन गई थी, लेकिन इसको अनदेखा करके भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं ने अनुच्छेद 370 की ही रट लगाए रखी। ऐसे पेश आए जैसे अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध करना देशद्रोह के समान हो।

देशभक्ति एक ऐसी भावना है, जो दिल से निकलती है, उसे जबदस्ती नहीं थोपा जा सकता। मगर मोदी के इस दूसरे शासनकाल में देशभक्ति को जबदस्ती थोपने की लगातार कोशिश होती आई है। कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाना जैसे परीक्षा बन गई है देशभक्ति की, बिना यह देखे कि जो लोग इस विशेष दर्जे को हटाए जाने के पक्ष में हैं उनको भी अब चिंता होने लगी है कि कश्मीर घाटी में शांति बहाल करने के लिए मोदी सरकार की कोई रणनीति है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

# आधी थाली की उदासी

थे, जबकि भाजपा अहंकार और प्रचार में बह गई थी। जनता चतुर है। उसने सबको संतुलन में ला दिया। यह एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत है।

इसके बाद के सीन कुछ अजीब दिखे। जिस वक्त फडणवीस बोल रहे थे, ठीक उसी वक्त पीएम वाराणसी के लोगों को संबोधित करते दिखे। हम समझे कि अब चैनल पीएम के संबोधन को वरीयता देंगे, लेकिन ऐसा न हुआ। कई चैनलों ने ‘स्प्लिट स्क्रीन’ करके दिखाना शुरू किया। लेकिन कई चैनलों में फडणवीस बोलते दिखते रहे और पीएम को साइलेंट

### बारम्बर

- सुशील पन्नीरी**

सबसे सर्धात्मक दृश्य महाराष्ट्र के चुनावों के बाद दिखे। पहले उद्भव ठाकरे ने प्रेस को बताया कि पिछले चुनाव के पहले भाजपा अध्यक्ष घर आए थे, तब उनके साथ महाराष्ट्र में ‘फिफ्टी-फिफ्टी सीएम’ वाले फार्मूले पर सहमति हुई थी। हम उस पर कायम हैं। दिखाते रहे! हमें तो यह शुद्ध बदतमीजी लगी! इन परिणामों ने बेचारे लड्डुओं को एकदम भूमिका विहीन कर दिया। सुबह सुबह एक हिंदी चैनल एक जगह बड़े उत्साह से बहुत से लड्डू बनते दिखा रहा था, लेकिन शाम तक उसने भी लड्डुओं की थालियां तक गावब कर दीं! सिर्फ मुंबई में कुछ पटाखे फटते और ढोल बजते सुनाई दिए, लेकिन हरियाणा में न लड्डू दिखे, न बहुत ढोल-गुनाइ! शायद इसी वजह से भाजपा कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने के लिए भाजपा के मुख्यालय में एक धन्यवाद सभा की गई, जिसमें भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने कार्यकर्ताओं को प्रबोधा। पहली बार कार्यकर्ताओं में पुराने वाला वह जोश-खरोश नहीं

### इसका अंतरराष्ट्रीयकरण हो चुका है। जब तक कश्मीर के बड़े राजनेता नजरबंद रहते हैं, जब तक घाटी में कर्फ्यू हर दूसरे दिन लगात रहता है, तब तक दुनिया सवाल उठाती रहेगी और भारत की बदनामी होती रहेगी, जैसे वॉशिंगटन में पिछले सप्ताह तब हुई जब अमेरिका की एक कांग्रेस समिति ने दक्षिण एशिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चर्चा की। चर्चा सिर्फ कश्मीर

घाटी पर हुई। न किसी ने बलूचिस्तान का जिक्र किया और न ही किसी ने ध्यान दिलाया पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म की तरफ। सिर्फ कश्मीर की बातें हुईं, जिनको सुन कर ऐसा लगा कि भारत एक ऐसा देश है, जिसमें लोकतंत्र नहीं तानाशाही है। ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी, जब तक कश्मीर घाटी में शांति बहाल नहीं होती और वह तभी होगी जब आम कश्मीरी को महसूस होने लगेगा कि वास्तव में अनुच्छेद 370 के हटने से उसकी भलाई है। तब तक मोदी सरकार की कश्मीर नीति पर सवाल पूछे जाएंगे।

महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हथियार बना कर इस्तेमाल करना गलत था। ऐसा करने से सवाल पूछने वालों की तादाद बढ़ी है। मेरी राय है कि

इस अनुच्छेद को कभी न कभी तो हटाना ही जाना था, लेकिन मुझे भी चिंता होने लगी है कि अगले कदम के बारे में मोदी सरकार ने अभी तक सोचा ही नहीं है। कभी न कभी तो कर्फ्यू हटाना पड़ेगा घाटी से, कभी न कभी तो कश्मीर के बड़े राजनेताओं को रिहा करना पड़ेगा, तब क्या होगा? क्या कोई रणनीति बनी है शांति वापस लाने की? इन सवालों का वास्ता कश्मीर से है, किसी अन्य राज्य के चुनावों से नहीं।

हर राज्य के अपने स्थानीय मुद्दे होते हैं, जिनको उठाए बगर चुनाव बेमतलब से हो जाते हैं आम मतदाता की नजरों में। सो, ऐसा हुआ है इन विधानसभा चुनावों में और पहली बार ऐसा लगने लगा है कि मोदी-शाह के आलीशान चुनावी रथ में थोड़ी-सो कमजोरी आ गई है। नहीं आई होती, तो लोकसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करने के कुछ ही महीनों बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में कमजोरियां न दिखने लगी होतीं।

इसका अंतरराष्ट्रीयकरण हो चुका है। जब तक कश्मीर के बड़े राजनेता नजरबंद रहते हैं, जब तक घाटी में कर्फ्यू हर दूसरे दिन लगात रहता है, तब तक दुनिया सवाल उठाती रहेगी और भारत की बदनामी होती रहेगी, जैसे वॉशिंगटन में पिछले सप्ताह तब हुई जब अमेरिका की एक कांग्रेस समिति ने दक्षिण एशिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चर्चा की। चर्चा सिर्फ कश्मीर घाटी पर हुई। न किसी ने बलूचिस्तान का जिक्र किया और न ही किसी ने ध्यान दिलाया पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म की तरफ। सिर्फ कश्मीर की बातें हुईं, जिनको सुन कर ऐसा लगा कि भारत एक ऐसा देश है, जिसमें लोकतंत्र नहीं तानाशाही है। ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी, जब तक कश्मीर घाटी में शांति बहाल नहीं होती और वह तभी होगी जब आम कश्मीरी को महसूस होने लगेगा कि वास्तव में अनुच्छेद 370 के हटने से उसकी भलाई है। तब तक मोदी सरकार की कश्मीर नीति पर सवाल पूछे जाएंगे।

महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हथियार बना कर इस्तेमाल करना गलत था। ऐसा करने से सवाल पूछने वालों की तादाद बढ़ी है। मेरी राय है कि

इस अनुच्छेद को कभी न कभी तो हटाना ही जाना था, लेकिन मुझे भी चिंता होने लगी है कि अगले कदम के बारे में मोदी सरकार ने अभी तक सोचा ही नहीं है। कभी न कभी तो कर्फ्यू हटाना पड़ेगा घाटी से, कभी न कभी तो कश्मीर के बड़े राजनेताओं को रिहा करना पड़ेगा, तब क्या होगा? क्या कोई रणनीति बनी है शांति वापस लाने की? इन सवालों का वास्ता कश्मीर से है, किसी अन्य राज्य के चुनावों से नहीं।

हर राज्य के अपने स्थानीय मुद्दे होते हैं, जिनको उठाए बगर चुनाव बेमतलब से हो जाते हैं आम मतदाता की नजरों में। सो, ऐसा हुआ है इन विधानसभा चुनावों में और पहली बार ऐसा लगने लगा है कि मोदी-शाह के आलीशान चुनावी रथ में थोड़ी-सो कमजोरी आ गई है। नहीं आई होती, तो लोकसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करने के कुछ ही महीनों बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में कमजोरियां न दिखने लगी होतीं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।

कश्मीर को अब हम अपना घरेलू मुद्दा नहीं कह सकते हैं।